



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 10 अगस्त, 2005/19 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

शिमला-2, 10 अगस्त, 2005

संख्या: वि० स०- विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-53/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन निम्नावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन

का विनियमन और नियन्त्रण) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक 21) जो आज दिनांक 10 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, संसदाधरण की सूचनाथे राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

भूगर्भ जल के विकास और प्रबन्धन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए तथा उसमें सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के लगभग नौ वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 है ।

संक्षिप्त
नाम और
प्रारम्भ ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि मन्दभंग में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 है ;

(ख) "भूगर्भ जल के लिए कृत्रिम पुनः प्रभरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा भूगर्भ जल जलाशय का पुनः पूर्ति की प्राकृतिक स्थिति में पड़े संवर्धन किया जाता है ;

(ग) "प्राधिकरण" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) "पेयजल" से पीने और अन्य घरेलू प्रयोजनों के लिए मानव आबादी द्वारा उपभोग या उपयोग के लिए जल अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत खाना पकाने, नहाने, धोने, सफाई करने तथा अन्य दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलापों के लिए जल का उपभोग या उपयोग आया और इसके अन्तर्गत पशुधन के उपभोग के लिए जल भी होगा ;

(ङ) "विदोहन सीमा" से ऐसी सीमा अभिप्रेत है जहां प्राकृतिक वार्षिक भूगर्भ जल का निकालना प्राकृतिक औसत वार्षिक भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण से पच्चासी प्रतिशत से अधिक है ;

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(छ) "भूगर्भ जल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह से नीचे विद्यमान है और जिसे कुओं या किसी अन्य साधनों से निकाला जा सकता है या जो जल धाराओं और नदियों में झरनों और मुख्य प्रवाहों के रूप में निकलता है ;

(ज) "अधिसूचित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 5(5) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है ;

- (अ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;
- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (ट) "वर्षा जल संचयन" से वर्षा जल का सतह पर या उप-सतही जल भर में संग्रहण और भण्डारण की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;
- (ठ) "रायलेटी" से इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार को संदेय रायलेटी अभिप्रेत है ;
- (ड) कुएं के सम्बन्ध में "खुदाई" से इसकी समस्त व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय पद सहित नए कुओं का कोई उत्खनन, ड्रिलिंग या बोरिंग या विद्यमान कुओं को गहरा करना है ;
- (ढ) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;
- (ण) "भूगर्भ जल उपयोक्ता" से किसी कम्पनी या किसी उद्योग या किसी स्थापन, चाहे सरकारी हो या न हो सहित कोई व्यक्ति या संस्थान अभिप्रेत है जो घरेलू उपयोग को अपवर्जित करके किसी भी प्रयोजन के लिए भूगर्भ जल का उपयोग करता है ; और
- (न) "कुंआ" से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा भूगर्भ जल स्रोतों के सर्वेक्षण और मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों, समन्वयण, विकास या प्रबन्ध कार्य के क्रियान्वयन या सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए खोदे गए कुएं के सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा भूगर्भ जल की खोज या उसे निकालने के लिए खोदी गई संरचना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खुला कुंआ, खुदा कुंआ, वेधित कुंआ, खुदा एवं वेधित कुंआ, ट्यूबवैल, फिल्टर प्वाइंट, संग्राहक कुंआ, अन्तःसारण गैलरी, पुनःप्रभरण कुंआ, विन्यास कुंआ या उनमें से किसी का संयोजन या रूप भेद है सिवाय भूगर्भ जल निस्सारण के लिए किसी भी हस्तसाधित युक्ति के ।

प्राधिकरण
की स्था-
पना ।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिमूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश "भूगर्भ जल प्राधिकरण" के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी ।

(2) भूगर्भ जल प्राधिकरण के निम्नलिखित सदस्य होंगे.—

- (i) इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, हिमाचल प्रदेश .. अध्यक्ष
- (ii) प्रधान मुख्य श्रण्यपाल वन, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
- (iii) निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
- (iv) निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
- (v) निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य
- (vi) प्रमुख, सूदूर संवेदी कक्ष, हिमाचल प्रदेश .. सदस्य

- (vii) सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड । सदस्य
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (बोर्ड) का नाम निर्देशिनी सदस्य
- (ix) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड सदस्य
- (x) अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण युनिट-II), बिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग । सदस्य
मविब, ग्री
- (xi) पांच से अधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार की राय में भूगर्भ जल स्त्रोतों के प्रवन्ध से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों ।
- (3) सदस्य अध्यक्ष को सलाह देंगे जोकि प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होगा ।
- (4) प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला में होगा ।

4. राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ ऐसी संख्या में तकनीकी व्यक्ति और अन्य कर्मचारि-
वृन्द तैनात कर सकेगी जैसे वह आवश्यक समझे ।

प्राधिकरण
के कर्मचारि-
वृन्द ।

5. (1) प्राधिकरण राज्य सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

(2) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी रूप में भूगर्भ जल के निकालने को नियन्त्रित करना या विनियमित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है, तो यह राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए परामर्श देगा ।

(3) राज्य सरकार उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त प्राधिकरण की सलाह का परीक्षण करने के पश्चात् तथा ऐसी और जंच करने के पश्चात्, जैसी यह उचित समझे, ऐसे क्षेत्र या उसके भाग को अधिसूचित क्षेत्र द्वारा उसी तारीख में जैसी राज्य विनियमित की जाए, अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगी :

भूगर्भ जल
के विकास
और प्रवन्धन
के विनियम
और नियंत्रण
के लिए
क्षेत्रों को
अधिसूचित
करने की
शक्ति ।

परन्तु यह कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र को, इस धारा के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अधिसूचित करने के अपने आणख को घोषित कर सकेगी, यदि आवश्यक समझे ।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक ऐसी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के साथ-साथ राज्य में व्यापक परिचालन करने वाले कम से कम दो दैनिक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी और उक्त क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों के कार्यालयों और परिक्षेत्र के सहज दृश्य स्थानों पर अधिसूचना की एक प्रति की चिपकाकर भी इसकी तामील की जाएगी ।

(5) उप-धारा (3) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी घोषणा के विरुद्ध राज्य सरकार को आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे, जो इसके द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् तीस दिन के भीतर विनिश्चित किए जाएंगे और तत्पश्चात् तीस दिन के भीतर अन्तिम अधिसूचना जारी की जाएगी ।

(6) यदि प्राधिकरण की राय में किसी अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है तो यह राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई क्षेत्र करने का परामर्श दे सकेगी और राज्य सरकार उसी रीति में, ऐसे क्षेत्र को डी-नोटिफाई कर सकेगी ।

(7) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि भूगर्भ जल संसाधनों का दोहन जलधरो की प्राकृतिक पुनः पूर्ति से अधिक न हो और जहां कहीं भी असमानता है वहां

विनियामक उपायों के अतिरिक्त भूगर्भ जल संसाधनों का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा।

प्राधिकरण द्वारा भूगर्भ जल पर डेटा बेस अनु-रक्षित रखना।

6. प्राधिकरण राज्य के भूगर्भ जल स्रोतों पर डेटा बेस अनुरक्षित रखेगा और अद्यतन करेगा।

भूगर्भ जल को निकालने और उसका उपयोग करने के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करना।

7. (1) भूगर्भ जल का कोई भी उपयोक्ता जो किसी भी प्रयोजन के लिए अधिसूचित क्षेत्र के भीतर कुआं खुदवाना चाहता है तो वह ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, प्राधिकरण को अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसी खुदाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई क्रियाकलाप तब तक नहीं करेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान नहीं कर दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी विशिष्टियों से अन्तर्विष्ट होगा जैसी विहित की जाएं।

(3) प्राधिकरण उप-धारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करेगा और यदि उम्मीद समाधान हो जाता है तो वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, अनुज्ञापत्र प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण आवेदन पर विचार करते समय, अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः पेयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगा :

परन्तु यह और कि मुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी अनुज्ञापत्र को नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(4) अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने से सम्बन्धित विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, आवेदक को सूचित किया जाएगा।

(5) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने या नामंजूर करने के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा—

- (क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए जल का उपयोग किया जाएगा ;
- (ख) अन्य स्पर्धी उपयोक्ताओं की विद्यमानता ;
- (ग) जल की उपलब्धता ;
- (घ) प्रस्तावित उपयोग के सन्दर्भ में निकासी लिए जाने वाले भूगर्भ जल की गुणवत्ता ;
- (ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाना है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन ;
- (च) यथास्थिति, विद्यमान उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम या उठाऊ सिंचाई स्कीम से उथले कुंओं की दशा में कम से कम दो मी मीटर और ट्यूबवैल की दशा में कम से कम तीन सौ मीटर की दूरी ;

(छ) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार ; और

(ज) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक ।

8. (1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, प्राधिकरण के गठन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, जिसमें ऐसी विशिष्टियाँ और फीस अन्तर्विष्ट हों, जैसी विहित की जाएँ, प्राधिकरण को, इसके विद्यमान उपयोग की मान्यता के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा :

भूगर्भ जल के विद्यमान उपयोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण ।

परन्तु, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि उपयोक्ता को समय के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह साठ दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, यदि प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो वह ऐसी शर्तों और निबन्धनों, जैसे उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएँ, के अधीन ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करते समय अन्य आवश्यकताओं की अधिमानतः देयजल आवश्यकताओं को प्रथम प्राथमिकता देगा :

परन्तु यह और कि सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र नामंजूर नहीं किया जाएगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को मंजूर करने या नामंजूर करने के विनिश्चय की सूचना, प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आवेदक को देनी होगी ।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर करने या नामंजूर करने में प्राधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा—

(क) प्रयोजन जिसके या जिनके लिए पानी का उपयोग किया जाना है ;

(ख) अन्य रूपों में उपयोक्ताओं की विद्यमानता ;

(ग) भूगर्भ जल की उपलब्धता ;

(घ) उपयोग के सन्दर्भ में भूगर्भ जल की गुणवत्ता ;

(ङ) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाना है को ध्यान में रखते हुए भूगर्भ जल निकालने की संरचनाओं का अन्तरालन ;

(च) दीर्घकालिक भूगर्भ जल स्तर व्यवहार ; और

(छ) इससे सुसंगत कोई अन्य कारक ।

(5) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक विद्यमान उपयोक्ता, उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकरण के लगभग विनिश्चय के दौरान भूगर्भ जल का उसी रीति में और उसी मात्रा में लगातार उपयोग करने का हकदार होगा, जिस प्रकार वह उसके लिए आवेदन की तारीख से पूर्व हकदार था।

(6) यदि रजिस्ट्रीकृत कुआँ निष्क्रिय हो जाता है, तो यह तथ्य भूगर्भ जल के उपयोक्ता द्वारा तुरन्त प्राधिकरण के नोटिस में लाया जाएगा और ऐसा कुआँ, यदि प्राधिकरण की राय में उपयुक्त पाया जाता है, भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण (रिचार्जिंग) हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

ट्रिलिंग
अधिकरणों
का रजि-
स्ट्रीकरण।

9. राज्य में क्रियाशील प्रत्येक रिग का स्वामी अपनी मशीनरी को प्राधिकरण के पास ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर करवाएगा और प्राधिकरण द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुसरण करेगा।

अनुज्ञापत्र
या रजिस्ट्री-
करण
प्रमाण-पत्र
के निबन्धनों
में परिवर्तन
करने, संशो-
धन करने
या फेरफार
करने की
शक्ति।

10. यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पश्चात् किसी भी समय, प्राधिकरण कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबन्धनों में परिवर्तन, संशोधन या फेरफार कर सकेगा :

परन्तु, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक कि भूगर्भ जल के उपयोक्ता को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता :

परन्तु यह और भी कि ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि खड़ी फसल (फसलों) को नुकसान न हो।

अनुज्ञापत्र/
और रजि-
स्ट्रीकरण
प्रमाण-पत्र
का
रद्दकरण।

11. यदि प्राधिकरण का इस निमित्त इस्तेमाल किया गया निर्देश द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) यथास्थिति, धारा 7 की उप-धारा (3) या धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तथ्यों पर आधारित नहीं है, या

(ख) अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या धारक व्यक्तिगत हेतु के बिना उन शर्तों की अनुपालना करने में, जिनके अधीन अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, असफल रहा है या उसने अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, या

(ग) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिससे भूगर्भ जल के उपयोग या उसका निकालना सीमित किया गया है, तो, किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो, प्राधिकरण, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथास्थिति, अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर सकेगा।

12(1) अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता, भूगर्भ जल को निकालने की रायलेटी ऐसी दरों पर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, राज्य सरकार को संदत्त करेगा :

भूगर्भ जल के उपयोग की वास्तविक रायलेटी ।

परन्तु यह कि भूगर्भ जल का उपयोक्ता जो, एक हैबिटेयर से कम भूमि, जो चाहे अपने स्वामीत्वाधीन हो या पट्टे पर हो या दोनों, की भिन्नाई करता है, तो उसे इस धारा के अधीन रायलेटी के संदाय से छूट होगी ।

(2) राज्य सरकार रायलेटी का ऐसा अनुपात, जैसा विहित किया जाए, भूगर्भ जल स्त्रोतों के विकास के लिए समनुदेशित कर सकेगी ।

13. (1) प्राधिकरण या इस निमित्त इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

प्राधिकरण की शक्तियाँ ।

(क) कुएं का निरीक्षण करना जिसकी खुदाई हो चुकी है या हो रही है और उसमें उत्खनित मिट्टी और अन्य सामग्रियों का निरीक्षण करना ;

(ख) ऐसे कुओं से निकाली गई ऐसी मिट्टी या अन्य सामग्रियों के या जल के नमूने लेना ;

(ग) लिखित में आदेश द्वारा, कुओं खोद रहे व्यक्ति से विहित रीति में उससे उत्खनित मिट्टी या अन्य किसी सामग्री के नमूनों को ऐसे कार्य की पूर्णता या परिष्करण की तारीख से तीन मास की ऐसी अनधिक अवधि, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए विहित रीति में रखने या परिष्कृत करने की अपेक्षा करना और तदुपरि, ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करेगा ;

(घ) सुसंगत अभिलेख या दस्तावेजों का निरीक्षण करना और उनकी प्रतियाँ लेना और खूद रहे या खोदे जा चुके कुएं के व्यास या गहराई सहित किसी सूचना को प्राप्त करना ; स्तर जिस पर जल आक्रान्त हुआ है या हुआ था तथा तत्पश्चात् प्रत्यानीत/निश्चल हुआ है, कुएं का खुदाई से प्राप्त स्ट्रैटा के प्रकार और प्रत्यानीत जल की गुणवत्ता जो इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है ;

(ङ) अवैध खुदाई (सिकिंग) के लिए प्रयुक्त किंसा उपस्कर या साधन (डिवाइस) का अधिग्रहण करना और निष्पादित किए गए कार्यों को पूर्णतः या भागतः नष्ट करना ;

(च) भूगर्भ जल के किसी उपयोक्ता, जो इस अधिनियम के उपबन्धों का या तद्धीन बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है, को आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाए गए नियमों का उत्तलंघन करने पर किसी जल आपूर्ति को बन्द करने या किसी जलीय (हाइड्रोलिक) कार्य को नष्ट करने की अपेक्षा करना ;

परन्तु जहाँ भूगर्भ जल का उपयोक्ता ऐसे आदेशों का, उन्हें जारी करने की तारीख से साठ दिन के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य का कार्यान्वित कर सकेगा और भूगर्भ जल के ऐसे उपयोक्ता से इसकी लागत वसूल कर सकेगा ;

(छ) किसी स्थान, जिसमें यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, में ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना और तलाशी लेना और व्यक्ति, जिसने अपराध किया है या कर रहा है, को लिखित में आदेश देना कि वह तीस दिन से अधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए भूगर्भ जल नहीं निकालेगा ;

(ज) किसी समुचित निकाय को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भूगर्भ जल के विदोहन की सीमा का निर्धारण करने के लिए निदेश देना और प्राधिकरण के विचारार्थ समय-समय पर रिपोर्ट देना ;

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति में किसी भी परिसर के, जहां पर भूगर्भ जल की सिंकिंग, निकालना और उपयोग चल रहा हो, दरवाजे तोड़कर खोलने की शक्ति भी सम्मिलित है :

परन्तु दरवाजे को तोड़कर खोलने की शक्ति का प्रयोग परिसर के स्वामी या उसके अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति, यदि वह वहां उपस्थित है द्वारा, ऐसा करने के लिए कहने पर भी दरवाजे को खोलने से इन्कार करने पर ही किया जाएगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिगृहण के लिए उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार उक्त संहिता की धारा 93 के अधीन जारी वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिगृहण का लागू है।

1974 का 2

(4) जहां प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन किसी यांत्रिक उपस्कर या साधन को अभिगृहित करता है तो वह यथाशक्य शीघ्र अधिकांशता रखने वाले मैजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और उसकी अभिरक्षा के लिए उसका आदेश लेगा।

मापन यन्त्रों
का लगाया
जाना।

14. भूगर्भ जल का प्रत्येक उपयोक्ता अधिसूचित क्षेत्र में, यथास्थिति, धारा 7 या 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भूगर्भ जल निकालने की प्रवर्तन-चर्या पर जल मापन यन्त्र लगाएगा :

परन्तु यह कि जहां भूगर्भ जल का उपयोक्ता इस धारा के अधीन उपबन्धों का तीस दिन की अवधि के भीतर पालन नहीं करता है, तो प्राधिकरण या इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, ऐसा जल मापन यन्त्र लगाएगा और भूगर्भ जल के व्यतिक्रमी उपयोक्ता से उसकी लागत वसूल कर सकेगा।

संरक्षण और
भूगर्भ जल
पुनः प्रभरण
हेतु वर्षा जल
का संचयन।

15. (1) प्राधिकरण, भूगर्भ जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए भूगर्भ जल पुनः प्रभरण के क्षेत्रों की पहचान कर सकेगा और ऐसे क्षेत्रों में भूगर्भ जल प्रभरण हेतु वर्षा जल के संचयन को अपनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर समस्त विकासक स्कीमों में वर्षा जल के संचयन को सम्मिलित करने के निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में सी वर्ग मीटर या इससे अधिक के चौकी क्षेत्र (पल्लिय एरिया) वाले आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य परिसरों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं विनिर्मित करने के लिए निर्देश ऐसी रीति में जारी करेगा, जैसी विज्ञान की जाए और इस प्रकार जारी निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में, ऐसे वर्षा जल संचयन विनिर्माण, प्राधिकरण द्वारा विनिर्मित किए जाएंगे और उनकी लागत ऐसी प्राप्ति महित, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, वसूल की जाएगी।

(4) प्राधिकरण, यथास्थित, नगर निगम या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सी वर्ग मीटर या इससे अधिक के चौकी क्षेत्र (पल्लिय एरिया) के भवनों के रेखांकों (प्लानज) में छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं की व्यवस्था के लिए नियत शर्तें अधिरोपित करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश या दिए गए नोटिस की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात्:—

आदेशों की तामील, इत्यादि।

(क) भूगर्भ जल के उपयोक्ता को आदेश या नोटिस की प्रति देकर या निविदान करके, इसे डाक द्वारा भेजकर, यदि भूगर्भ जल का ऐसा उपयोक्ता नहीं मिलता है तो ऐसे आदेश या नोटिस की प्रति को उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य या उसके सेवक को देकर या निविदान करके;

(ख) यदि ऐसे आदेश या नोटिस की तामील खण्ड (क) के अधीन प्रभावी नहीं की जा सकती है तो ऐसे आदेश की प्रति उसके अन्तिम ज्ञात निवास या कारबार के किसी सहजदृश्य स्थान पर या भूमि या भवन के किसी भाग, जिसमें कुआं खोदा जा रहा है, पर चिपका कर, की जाएगी।

(2) जहां व्यक्ति, जिसे आदेश या नोटिस की तामील की जानी है, अवस्थित हो तो उसके संरक्षक पर, उप-धारा (1) में उपबन्धित रीति में ऐसे आदेश या नोटिस की तामील, अवस्थित पर की गई समझी जाएगी।

17. राज्य सरकार साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि सभी या किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों, जिनका प्रयोग या निर्वहन प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा, का प्रयोग या निर्वहन, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जैसी इसके आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायो-जन।

18. प्राधिकरण के सभी सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहें हों या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

19. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आवश्यक किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के किसी अधिकारी/कर्मचारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएगी।

सद्भाव-पूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण।

अपराधों का संज्ञान और विचारण। 20. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित शिकायत के बिना विचारण नहीं किया जाएगा।

(2) प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अपराध और शास्तियां। 21. (1) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या प्राधिकरण को या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को बाधित करता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा तथा दूसरे और पञ्चात्वर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) यदि भूगर्भ जल का कोई उपयोक्ता, इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में कुआं खोदता है, निमित्त करता है या उसका प्रयोग करता है तो वह प्रथम अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से तथा दूसरे और पञ्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराधों का शमन। 22. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो तो ऐसे अपराध का, कार्य-वाहियां संस्थित करने से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इसके शमन स्वरूप, ऐसी राशि स्वीकार कर, जो ऐसी रकम से अधिक न हो जो विहित की जाए, शमन किया जाएगा और ऐसे शमन का प्रभाव ऐसे व्यक्ति को अपराध से उन्मोचित करने वाला होगा और अपराध, जिसका इस प्रकार शमन किया गया है, की बावत उसके विरुद्ध और कोई कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी।

कम्पनियों द्वारा अपराध। 23. (1) जब कभी इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार साधक या उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौन-नुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भी भागी होगा।

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध, उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब-सम्भक तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और (ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

24. (1) इस अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर जैसी विहित की जाए, प्राधिकरण को अपील करेगा ।

परन्तु यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर राज्य सरकार अपीलार्थी को मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्रता के साथ अपील का निपटारा करेगी, किन्तु छः मास के पश्चात्, और राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

25. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिमूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के जिनमें वे इस प्रकार रखे गए हों । या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या सहमत हो जाती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथाशक्ति, ऐसा निम्न दो परिणति में प्रभावी होगा : यदि उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । तथापि ऐसे किसी परिणति या वास्तविक कारण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जल एक समीक्षात्मक स्रोत है जो धारणीय विकास की सीमाओं को परिभाषित करता है। इसका कोई भी विकल्प नहीं है और मानवीय मांगों और उपलब्ध मात्रा के मध्य अनिवार्य सन्तुलन है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही जल उपलब्धता के विषय निरन्तर अग्रणीय (फोरफ्रंट) में बने रहेंगे।

राज्य के कृषिपय क्षेत्रों में, यह देखा गया है कि भूगर्भ जलाशय आधारित जल स्रोतों का पुनःप्रभरण निस्सारित किये जा रहे भूगर्भ जल से काफी निम्नतर है। यह एक चिन्ता का विषय है क्योंकि भूगर्भ जल स्रोतों का अत्यधिक विदोहन जल भरणों का निःशेषण करता है और समसामयिक रूप से भूगर्भ जल में अस्वीकार्य रासायनिक संघटकों के बहाव के कारण इसमें जन गुणवत्ता को निम्नीकृत करता है। इसलिए, विशेषकर जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जल सारणी (वाटर टेबल) के स्थायित्व को जोखिम में डालने से बचाने के लिए, भूगर्भ जल की पम्पिंग को स्वविवेक और वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध किया जाना है।

जल सारणी (वाटर टेबल) की गिरावट को रोकने, और इसका वांछनीय स्तरों पर अनुरक्षण करने हेतु विधि द्वारा भूगर्भ जल के निस्सारण को विनियमित करना और नियन्त्रित करना अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूगर्भ जल की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। बेहतर भूगर्भ जल पुनः प्रभरण के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से संरक्षण की अभिवृद्धि करना अनिवार्य है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में, छतों से वर्षा जल को भूगर्भ जल पुनःप्रभरण हेतु काम में लाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, वाटरशेड हेतु संरक्षण उपायों में, गली प्लग, कनट्रोलर बन्ध, ग्रेविटेशन अवसंरचना, चैक डैम/बन्ध, परकलेशन टैंक, पुनः प्रभरण साफ्ट इत्यादि हो सकते हैं। इसलिए, भूगर्भ जल के निस्सारण को विनियमित करने और नियन्त्रित करने के साथ-साथ पुनः प्रभरण प्रक्रिया की अभिवृद्धि करने, ताकि इसकी उपलब्धता में सुधार हो, के लिए विधान के माध्यम से निर्वन्धन अभिरोपित करना लोकहित में है।

यह विधेयक भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापना, भूगर्भ जल के उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण, अधिसूचित क्षेत्रों में अनुज्ञापत्रों की प्रदान करने, भूगर्भ जल के पुनः प्रभरण हेतु वर्षा जल संचयन, फीस और रायलेटी के संदाय और अपराधों का जमान करने का उपबन्ध करता है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति का भी उपबन्ध करता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रचारी मन्त्री।

निमला :

तारीख : 2005.

वित्तीय जापन

विधेयक का खण्ड 3 इस विधान के कार्यान्वयन का निरोक्षण करने हेतु पन्द्रह मदस्थीय हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए है। प्राधिकरण की स्थापना और कार्यालय खर्च और इसके समर्थक कर्मचारिवृन्द पर सम्भाव्य व्यय लगभग बीस लाख रुपये प्रतिवर्ष होने का अनुमान है। इसके साथ-साथ विधेयक के खण्ड 7 और 8 भूगर्भ जल उपयोगताओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्राधिकरण की फीस के संदाय का उपबन्ध करते हैं और खण्ड 12 वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रयोजनों हेतु भूगर्भ जल निकालने के लिए राज्य सरकार को रायलेटी के संदाय का उपबन्ध करता है। इस विधेयक के उपबन्धों के अधिनियमित होने से राजकोष पर प्रतिवर्ष लगभग बीस लाख रुपये का अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्बलित होगा।

प्रत्यायोजित विधान सभाधी जापन

विधेयक का खण्ड 25, राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने हेतु, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[आई० पी० एच० विभाग मस्ति संख्या पी० बी० डब्ल्यू०(पी० एच०)ए०(3)-2/92-1]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) विधेयक, 2005 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियन्त्रण) विधेयक, 2005

भूगर्भ जल के विकास और प्रबंधन को विनियमित और नियन्त्रित करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

कौल सिंह ठाकुर,
प्रभारी मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख; 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 21 of 2005.

**THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION
AND CONTROL OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT)
BILL, 2005**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to regulate and control the development and management of ground water and matters connected therewith.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definition:

- (a) "Act" means the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2005;
- (b) "artificial recharge to ground water" means the process by which ground water reservoir is augmented beyond the natural condition of replenishment ;
- (c) "Authority" means the Himachal Pradesh Ground Water Authority established under section 3 of this Act ;
- (d) "drinking water" means water for consumption or use by human population for drinking and for other domestic purposes, which shall include consumption or use of water for cooking, bathing, washing, cleansing and other day-to-day activities and shall include water meant for consumption by the livestock ;
- (e) "exploitation limit" means such limit where the estimated annual ground water extraction is more than eighty-five percent of the estimated average annual ground water recharge ;
- (f) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh ;
- (g) "ground water" means the water which exists below the ground surface in the zone of saturation and can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers ;
- (h) "notified area" means the area notified under section 5 (5) of this Act ;
- (i) "Official Gazette" means the Rajpatra of Himachal Pradesh ;

- (j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (k) "rain water harvesting" is the process of collection and storage of rain water at surface or in sub-surface aquifer ;
- (l) "royalty" means the royalty payable to the State Government under section 12 of this Act ;
- (m) "sink" with all its grammatical variations and cognate expression in relation to a well includes any digging, drilling or boring of new wells or deepening of the existing wells ;
- (n) "State" means the State of Himachal Pradesh ;
- (o) "user of ground water" means a person or an institution including a company or an industry or an establishment, whether Government or not, who or which uses ground water for any purpose excluding domestic use ;
- (p) "well" means a structure sunk for the search or extraction of ground water by any person, except by the authorized officials of the State or Central Government, for carrying out scientific investigations, exploration, development, augmentation, conservation, protection or management of ground water and shall include open well, dug well, bore well, dug-cum-bore well, tubewell, filter point, collector well, infiltration gallery, recharge well, disposal well, or any of their combinations or variations, except any manually operated device for extraction of ground water.

Establish-
ment of the
Authority.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish, with effect from such date as may be specified in the notification, an Authority to be known as "The Himachal Pradesh Ground Water Authority".

- (2) The Authority shall have as members, —
- | | |
|---|--------------------------|
| (i) Engineer-in-Chief, Irrigation and Public Health, Himachal Pradesh | .. Chairman |
| (ii) Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh | .. Member |
| (iii) Director, Industries, Himachal Pradesh | .. Member |
| (iv) Director, Rural Development and Panchayati Raj Department, Himachal Pradesh | .. Member |
| (v) Director, Agriculture Department, Himachal Pradesh | .. Member |
| (vi) Head, Remote Sensing Cell, Himachal Pradesh | .. Member |
| (vii) Member Secretary, Pollution Control Board, Himachal Pradesh | .. Member |
| (viii) Nominee of Himachal Pradesh State Electricity Board | .. Member |
| (ix) Regional Director, Central Ground Water Board | .. Member |
| (x) Superintending Engineer (Planning and Investigation Unit-II), Irrigation and Public Health Department | .. Member-Secretary, and |

- (xi) Such other members not exceeding five, who in the opinion of the State Government have special knowledge or practical experience in matters relating to management of ground water resources.

(3) The members shall advise the Chairman who shall be the Chief Executive of the Authority.

(4) The headquarters of the Authority shall be at Shimla.

4. The State Government may deploy such number of technical personnel and other staff with the Authority as it may consider necessary.

Staff of the Authority.

5. (1) The Authority shall function under the overall control and supervision of the State Government.

Power to notify areas to regulate and control the development and management of ground water.

(2) If the Authority is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest to control and or regulate the extraction of ground water in any form in any area, it shall advise the State Government to declare any such area to be a notified area for the purposes of this Act.

(3) The State Government after examining the advice of the Authority, received under sub-section (2), and after making such further enquiry, as it may deem fit, may by notification, declare such area or part thereof to be the notified area, with effect from such date, as may be specified therein:

Provided that the State Government may *suo moto* by notification declare its intention to notify any area to be the notified area under this section, if deemed necessary.

(4) Every such notification issued under sub-section (3) shall, in addition to its publication in the Official Gazette, be published in not less than two daily regional language newspapers having wide circulation in the State and shall also be served by affixing a copy of the notification at the offices of the Gram Panchayats located in the said area and at some conspicuous places of the locality.

(5) The persons likely to be affected by the notification issued under sub-section (3), may file objections or suggestions within thirty days from the date of publication of the same in the Official Gazette, against such declaration to the State Government which shall be decided by it within thirty days, after public hearing and thereafter, final notification shall be issued within thirty days.

(6) If in the opinion of the Authority, the availability of the ground water has improved in a notified area, it may advise the State Government to denotify such area, and the State Government may in the like manner, denotify such area.

(7) The Authority shall take steps to ensure that exploitation of ground water resources does not exceed the natural replenishment to the aquifers and wherever, there is mismatch, steps shall be taken to ensure augmentation of ground water resources in addition to regulatory measures.

Authority
to maintain
data base on
ground
water.

6. The Authority shall maintain and update the data base on ground water resources of the State.

Grant of
permit to
extract and
use ground
water.

7. (1) Any user of ground water desiring to sink a well within notified area, for any purpose shall, on payment of such fee as may be prescribed, apply to the Authority for grant of a permit, and shall not proceed with any activity connected with such sinking unless a permit has been granted by the Authority.

(2) Every application made under sub-section (1) shall be in such form and contain such particulars as may be prescribed.

(3) The Authority shall consider the application made under sub-section (1) and if satisfied, may grant a permit, in such form as may be prescribed, subject to such conditions and restrictions as may be specified, within sixty days from the date of receipt of the application :

Provided that while considering the application the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no permit shall be refused without affording an opportunity of being heard.

(4) The decision regarding grant or refusal of the permit shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(5) In granting or refusing a permit under sub-section (3), the Authority shall have regard to—

- (a) the purpose or purposes for which water is to be used;
- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water ;
- (d) quality of ground water to be drawn with reference to proposed usage;
- (e) spacing of ground water structures keeping in view the purpose for which water is to be used;
- (f) minimum distance of two hundred meters in case of shallow well and three hundred meters in case of tube well from the existing source of water supply scheme or irrigation scheme, as the case may be;
- (g) long term ground water level behaviour; and
- (h) any other factor relevant thereto.

8. (1) Every existing user of ground water in a notified area shall, within a period of two months from the date of establishment of the Authority shall, make an application on such form containing such particulars and fees, as may be prescribed, to the Authority for the grant of certificate of registration recognizing its existing use:

Registration of existing users.

Provided that the Authority may entertain any such application after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the user was prevented by sufficient cause from filing application in time.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), if the Authority is satisfied that it shall not be against the public interest to do so, it shall grant, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, a certificate of registration in such form as may be prescribed authorising continued use of the ground water:

Provided that while considering the application, the Authority shall give first priority for drinking water needs in preference to other needs:

Provided further that no user of ground water shall be refused a certificate of registration without being given an opportunity of being heard.

(3) The decision regarding grant or refusal of the certificate of registration shall be intimated by the Authority to the applicant within a period of thirty days from the date of decision.

(4) In granting or refusing a certificate of registration under sub-section (2), the Authority shall have regard to,—

- (a) the purpose or purposes for which water is to be used;
- (b) the existence of other competitive users;
- (c) the availability of water;
- (d) quality of ground water with reference to its usage;
- (e) spacing of groundwater abstraction structures keeping in view the purpose for which water is to be used;
- (f) long term ground water level behaviour; and
- (g) any other factor relevant thereto.

(5) Every existing user of ground water in the notified area during pendency of decision of the Authority under sub-section (2) shall be entitled to the continued use of the ground water in the same manner and to the same quantity as he was entitled prior to the date of application.

(6) If a registered well becomes defunct, this fact shall be immediately brought to the notice of the Authority by the user of ground water and such well may be used for ground water recharging if in the opinion of the Authority it is found fit.

Registration of drilling agencies.

Power to alter, amend or vary the terms of the permit or certificate of registration.

Cancellation of permit/certificate of registration.

Royalty in respect of use of ground water.

Powers of the Authority.

9. Every rig owner operating in the State shall register his machinery with the Authority in such manner and on payment of such fee as may be prescribed and shall follow the instructions issued by the Authority.

10. At any time after a permit or certificate of registration, as the case may be, has been granted, the Authority may, for reasons to be recorded in writing, alter, amend or vary the terms of the permit or certificate of registration, as the case may be :

Provided that no change shall be made in the permit or certificate of registration, as the case may be, unless the user of ground water is afforded an opportunity of being heard :

Provided further that before taking such action, the Authority shall ensure that the standing crop(s) are not damaged.

11. If the Authority is satisfied either on a reference made to it in this behalf or otherwise that,—

- (a) the permit or certificate of registration granted, under sub-section (3) of section 7 or sub-section (2) of section 8 as the case may be, is not based on facts, or
- (b) the holder of the permit or certificate of registration has without reasonable cause failed to comply with the conditions subject to which the permit or certificate of registration has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or
- (c) a situation has arisen which warrants limiting of the use or extraction of ground water, then without prejudice to any other penalty to which the holder of the permit or of the certificate of registration may be liable under this Act, the Authority may after giving the holder of the permit or certificate of registration, as the case may be, an opportunity of being heard, cancel the permit or certificate of registration, as the case may be.

12. (1) Every user of ground water in a notified area shall pay to the State Government a royalty for extraction of ground water at such rates and in such manner as may be prescribed :

Provided that a user of ground water who irrigates less than one hectare of land, whether owned or leased or both, shall be exempted from payment of royalty under this section.

(2) The State Government may, assign such proportion of the royalty, as may be prescribed, for development of ground water resources.

13. (1) The Authority or any person authorized under section 17 of this Act in this behalf shall have the following powers, namely :—

- (a) to inspect the well, which has been or is being sunk and the soils and other materials excavated therefrom;
- (b) to take specimens of such soils or other materials or of water extracted from such wells;

- (c) to require, by order, in writing the person sinking a well to keep and preserve in the prescribed manner specimens of soil or any material excavated therefrom for such period not exceeding three months from the date of completion or abandonment of such work, as may be specified by the Authority, and thereupon such person shall comply with such order;
- (d) to inspect and to take copies of the relevant record or documents and seek any information including diameter or depth of the well which is being or has been sunk; the level at which the water is or was struck and subsequently restored/rested, the types of strata encountered in the sinking of the well and the quality of the water struck, required for carrying out the purposes of this Act;
- (e) to seize any equipment or device utilized for illegal sinking and destroy the work executed fully or partly;
- (f) to require, by order, any user of ground water who does not comply with the provisions of this Act or the rules made thereunder to close down any water supply or destroy any hydraulic work found to be in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder :

Provided that where the user of ground water does not comply with such order within a period of sixty days from the date of issue of the same, the Authority or any person authorized in this behalf may carry out the necessary work and recover the cost from such user of ground water;

- (g) to enter and search with such assistance, if any, as it considers necessary, any place in which it has reason to believe that offence under this Act has been or is being committed, and order, in writing, the person who has been or is committing the offence, not to extract ground water for a specified period not exceeding thirty days;
- (h) to direct an appropriate body to assess exploitation limit of ground water in different areas and submit periodic report for consideration of the Authority.
- (i) to exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or the rules made thereunder.

(2) The power conferred by this section includes the power to break open the door of any premises where sinking, extraction and use of ground water may be going on :

Provided that the power to break open the door shall be exercised only after the owner or any other person in occupation of the

premises, if he is present therein, refuses to open the door on being called to do so.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this section as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 93 of the said Code.

2 of 1974

(4) Where the Authority or any person authorised by it seizes any mechanical equipment or device under clause (e) of sub-section (1) it shall, as soon as may be, inform a Magistrate having jurisdiction and take his orders as to the custody thereof.

Installation
of measuring
devices.

14. Every user of ground water in a notified area shall install water measuring device on ground water abstraction structure within a period of thirty days from the date of registration under section 7 or 8, as the case may be :

Provided that where the user of ground water does not comply with the provisions of this section within a period of thirty days, the Authority or any person authorized in this behalf may install such water-measuring device and recover the cost from the defaulting user of ground water.

Rain water
harvesting
for conser-
vation and
ground-
water
recharge.

15. (1) The Authority may, in order to improve the ground water situation, identify the areas of ground water recharge and issue guidelines for adoption of rain water harvesting for ground water recharge in such areas.

(2) The Authority may, issue directions to the concerned departments of the State Government, to include rain water harvesting in all developmental schemes within notified areas.

(3) The Authority may, in urban areas, issue directions, in such manner as may be prescribed, for construction of rain water harvesting structures in residential, commercial and other premises having plinth area of 100 square meters or above and in the event of failure to comply with the directions so issued, such rain water harvesting structures shall be constructed by the Authority and the cost thereon shall be recovered along with such penalty in such manner as may be prescribed.

(4) The Authority may, issue directions to the Municipal Corporation or any other Local Authority, as the case may be, to impose stipulated conditions for providing roof top rain water harvesting structures in building plans with plinth area of 100 square meters or above.

Service of
orders etc.

16. (1) Every order or notice made under this Act shall be served in the following manner, namely :—

(a) by giving or tendering copy of the order or the notice by sending it by post to the user of ground water, if such user of

ground water cannot be found, by giving or tendering the copy of such order or notice to any adult member of his family or his servant;

- (b) if the service of such order or notice can not be effected under clause (a), by affixing the copy of such order or notice on some conspicuous place of his last known residence or place of business or on any part of the land or building in which the well is being sunk.

(2) Where the person on whom an order or a notice is to be served is a minor, service of such order or notice upon his guardian in the manner provided in sub-section (1), shall be deemed to be served upon the minor.

17. The State Government may, by general or special order in writing, direct that all or any of the powers and duties which may be exercised or discharged by the Authority shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in its order, be exercised by any person specified in such order.

Delegation of powers and duties.

18. All members and employees of the Authority shall when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Members and employees of the Authority to be public servants.

19. No prosecution, suit or other legal proceedings shall be instituted against any officer/official of the Government or any member or other employee of the Authority for anything done or intended to be done in good faith, under this Act, or the rules made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

20. (1) No prosecution for an offence under this Act shall be instituted except on a written complaint of the Authority or a person authorized in this behalf by the State Government.

Cognizance and trial of offences.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

21. (1) If any user of ground water fails to supply information required under the provisions of this Act or the rules made thereunder or obstructs the Authority or any other person authorised by the State Government to exercise any of the powers under this Act, he shall be punished for the first offence with fine which may extend to one thousand rupees and for the second and subsequent offence with fine which may extend to two thousand rupees.

Offences and penalties.

(2) If any user of ground water sink, constructs or uses well in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, he shall be punished for the first offence with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both and for the second and subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Compound-
ing of off-
ences.

22. Where any offence under this Act has been committed, such an offence may, at any time before or after the institution of proceedings, be compounded by the Authority, or any other officer authorised by the State Government after accepting by way of compensation thereof, a sum of money not exceeding such amount as may be prescribed, and such composition shall have the effect of discharging such person of the offence and no further proceedings shall be taken or continued against him in respect of the offence so compounded.

Offences by
Companies.

23. (1) Whenever an offence under this Act has been committed by a Company, every person who at the time of the commission of the offence was in charge of, or was responsible to the Company for the conduct of the business of the Company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the Company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under this Act, if he proves that offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation.—For the purpose of this section—

- (a) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Appeals.

24. (1) Any person aggrieved by an order of the officer exercising powers delegated under this Act may, within a period of thirty days from the date of such order, on payment of such fee as may be prescribed, prefer an appeal to the State Government:

Provided that the State Government may entertain an appeal after the expiry of said period of 30 days, if satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the State Government shall, after giving the appellant an opportunity of being heard, dispose of the appeal as expeditiously as possible but not later than six months and the decision of the State Government shall be final.

25. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, Assembly agrees in making any modifications in the rules or Assembly agrees that the rule should not be made, the rule thereafter, shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Water is the critical resource that defines the limits of sustainable development. It has no substitute, and there is a precarious balance between humanity's demands and the quantity available. As population grows, water availability issues will continue to remain in the forefront.

In some areas of the State it is seen that the natural recharge of under ground reservoir based water sources is far lower than the ground water being extracted. This is a matter of growing concern since over exploitation of ground water resources depletes the aquifers and simultaneously leads to degradation water quality therein due to the flow of unacceptable chemical constituents into the ground water. Therefore ground water pumping, especially in water scarce areas, has to be judiciously and scientifically managed to avoid jeopardizing the sustainability of the water table.

Regulation and control of ground water extraction by law is imperative to arrest the decline of the water table and maintain it at desirable levels. Moreover the necessity of improving the ground water situation in critical areas needs to be fostered. It is essential to promote conservation through better ground water recharge—naturally or artificially. Rain water from roof tops can be harnessed in urban and industrial areas for ground water recharge. In rural areas, conservation measures for a watershed could include construction of gully plugs, contour building, gabion structures, check dam/weir, percolation tank, recharge shaft etc. Thus it is in public interest to impose restrictions through legislation to regulate and control extraction of ground water as well as promote recharge activity so that availability improves.

The Bill seeks to provide for the establishment of a Ground Water Authority, registration of ground water users, grant of permits in notified areas, rain water harvesting for ground water recharge, payment of fees and royalty and composition of offences. Apart from this, Bill seeks to provide for penalty for contravention of the provisions of the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KAUL SINGH THAKUR.
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 3 of the Bill seeks to establish a fifteen members Himachal Pradesh Ground Water Authority to oversee the implementation of this legislation. The likely expenditure on the establishment and office expenses of the authority and its supporting staff is estimated at Rs. 20 Lacs per annum approximately. At the same time clauses 7 and 8 of the Bill provides for payment of fees to the Authority for registration of ground water users and clause 12 provides for payment of royalty to the State Government for extraction of ground water for commercial or industrial purposes. The provisions of this Bill, if enacted, shall involve additional recurring expenditure of Rs. 20 Lacs per annum approximately out of the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 25 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules, after previous publication, for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[I.P.H. Department File No. PBW (PH)A(3)-2/92-I]

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH GROUND WATER (REGULATION AND CONTROL
OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT) BILL, 2005

A

BILL

*to regulate and control the development and management of ground water and the matters
connected therewith.*

KAUL SINGH THAKUR,
Minister-In-charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The....., 2005

01/08/2005